बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 189 ● नई दिल्ली ● बुधवार 13 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

विनेश के आरोपों पर बृजभूषण का तीखा पलटवार, बोले- उस गंदगी को साफ कर रहे, जिसे उन्होंने पीछे छोड़ा

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में कार्रवाई जारी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक सदस्य का बयान दर्ज किया है। यह मामला भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। अदालत ने जांच अधिकारी का बयान दर्ज करने के लिए 15 और 19 मई की तारीख तय की है। कांग्रेस नेता और पहलवान विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह उस गंदगी को साफ कर रहे हैं, जिसे विनेश फोगाट ने पीछे छोड़ा है।

हिमंत बिस्वा सरमा को असम का सीएम बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, अद्भुत प्रशासक बताते हुए की जमकर तारीफ

असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ लेने पर डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक अद्भुत प्रशासक बताया और राज्य के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों की सराहना की। असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, असम के लिए बड़ा दिन! लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार कार्यभार संभाल रही है। डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा जी को शपथ लेने पर बधाई। उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने इन मंत्रियों को भी अलग से बधाई देते हुए कहा कि यह टीम असम की विकास यात्रा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। गुवाहाटी में आयोजित इस भव्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 22 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। समारोह की खास बात यह रही कि इसमें असम के वैष्णव मठों के 15 सत्राधिकार (धार्मिक गुरु) भी मौजूद रहे। इसके अलावा उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पारंपरिक असमिया परिधान में सजे हिमंत बिस्वा सरमा ने समर्थकों के भारी उत्साह के बीच शपथ ली। 2021 में पहली बार कमान संभालने के बाद, यह सरमा का दूसरा कार्यकाल है, जिसने पूर्वोत्तर भारत में भाजपा के राजनीतिक दबदबे को और अधिक सशक्त कर दिया है।

अब फ्लाइट या चार्टर्ड प्लेन से सफर नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र के मंत्री, पीएम की अपील के बाद सीएम फडणवीस का एक्शन

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बिना अब महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री को सरकारी विमान या चार्टर्ड विमान का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा खर्च नियंत्रण और ईंधन बचत पर जोर दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रियों की हवाई यात्राओं पर नियंत्रण रखने के लिए नई प्रशासनिक प्रक्रिया लागू की गई है। इसके तहत किसी भी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी को सरकारी विमान का उपयोग करना हो तो पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी मिलने के बाद ही विमान उपलब्ध कराया जाएगा।

पीएम मोदी की अपील के बाद तेज हुई कार्रवाई

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईंधन बचत, सरकारी खर्च में कटौती और संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग की अपील की थी। इसके बाद विभिन्न राज्यों में सरकारी खर्चों पर नियंत्रण को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थीं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिशा में अमल शुरू कर दिया है।

अनावश्यक हवाई यात्राओं पर लगेगी रोक

सरकारी सूत्रों के अनुसार, कुछ मंत्री कम दूरी के लिए भी विमान का उपयोग कर रहे थे। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। अब केवल अत्यावश्यक और आधिकारिक कार्यों के लिए ही विमान उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

खर्च नियंत्रण पर सरकार का फोकस

राज्य की आर्थिक स्थिति, बढ़ता राजस्व दबाव और विकास कार्यों के लिए आवश्यक निधि को देखते हुए सरकार खर्च नियंत्रण की नीति पर जोर दे रही है। सरकारी बैठकों, दौरों और यात्रा खर्चों में अनुशासन लाने के निर्देश भी विभिन्न विभागों को दिए गए हैं।

विपक्ष की प्रतिक्रिया संभव

सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोग इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की ओर से मंत्रियों के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा सकती है।

सांगली में मंदिर की दीवार और छत गिरने से छह श्रद्धालुओं की मौत, 12 घायल

सांगली। महाराष्ट्र के सांगली जिले में तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। इसने पूरे इलाके में मातम फैला दिया है। जिले के एक प्रसिद्ध मंदिर परिसर में अचानक एक दीवार और टिन की छतें गिर गईं। इस भयानक हादसे में दर्शन करने आए छह श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना मंगलवार शाम की है जब अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया और वह जानलेवा हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। मंदिर में दुर्घटना की सूचना मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक्स हैंडल पर जारी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के सांगली में दीवार गिरने से हुई जानमाल की हानि की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमओ पर ही जारी एक अन्य संदेश में प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा में भी बयान जारी किया। मंदिर में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुई यह दर्दनाक घटना सांगली जिले के जत तहसील में आने वाले मोरेवाड़ी गांव में हुई है। यहां गांव के मशहूर मारुदेवी मंदिर में लोग पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। मंगलवार शाम को इलाके में अचानक मौसम बदल गया और बहुत तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई।

अपने पतन की घोषणा है..., पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से की अपील तो बोले अखिलेश

प्रयागराज।

प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश के नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील पर प्रतिक्रिया दी. पीएम मोदी की अपील पर सपा चीफ अखिलेश यादव कहते हैं ने कहा कि यह कोई अपील नहीं है, बल्कि यह उनके अपने पतन की घोषणा है. आप संकट की बात करते हैं, जबकि संकट तो खुद बीजेपी ही है. सत्ता में कौन है? खुद बीजेपी ही है, जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था पर इतराते थे. आज अर्थव्यवस्था क्यों लड़खड़ा गई है? अर्थव्यवस्था पटरी से क्यों उतर गई है? उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े तो कुछ और ही दिखाते थे. पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश में मौजूदा हालात इस बात का संकेत देते हैं कि संकट खुद बीजेपी ही है. अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? अभी सत्ता में कौन लोग हैं? डॉलर का मूल्य क्यों गिर रहा है? ऐसी अपील जारी करना क्यों जरूरी हो गया है? यह कोई अपील नहीं है; यह तो पतन की अपील है.

> "पीएम मोदी की अपील पर सपा चीफ अखिलेश यादव कहते हैं ने कहा कि यह कोई अपील नहीं है, बल्कि यह उनके अपने पतन की घोषणा है. आप संकट की बात करते हैं, जबकि संकट तो खुद बीजेपी ही है. सत्ता में कौन है? खुद बीजेपी ही है, जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था पर इतराते थे. आज अर्थव्यवस्था क्यों लड़खड़ा गई है? अर्थव्यवस्था पटरी से क्यों उतर गई है?

तस्वीरें देखो किसके साथ है- अखिलेश यादव

वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोकसभा में हारे है वह अपील के बाद भी हारेंगे. वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या के मामले में यूपी से हुई गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा तस्वीरें देखो किसके साथ है, सबसे घटिया काम कोई कर सकता है वह ही कर सकते है...झांसी में कौन पकड़ा गया. बीजेपी के नेता 100 करोड़ के घोटालों में पकड़ा गया है. जिन लोगों के साथ उसकी तस्वीर थी वह खुद मुख्यमंत्री से मिलकर आए है कि यह निर्दोष है उसे बंगाल ने ले जाया जाए.

नीट का पेपर लीक, परीक्षा रद्द, अब जांच सीबीआई को

नई दिल्ली। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को नीट (यूजी) 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 3 मई को हुई थी। 22.79 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। एनटीए ने कहा कि अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। उधर, केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। उधर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में इस मामले में मीडिया ने सवाल पूछा तो वह बिना कुछ बोले निकल गए। 10 मई को राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कहा कि उसने नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। 12 मई तक सीकर और आसपास के इलाकों से 13 लोगों को अरेस्ट किया। 'क्वेश्चन बैंक' में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। ये सभी हाथ से लिखे गए और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। इसमें से 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है। यानी 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे 'क्वेश्चन बैंक' से आए। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी विशेष गेस पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती।

दोबारा होगी नीट परीक्षा, फिर से फीस नहीं देनी होगी, रिफंड भी मिलेगा

भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने 22 लाख छात्रों के सपनों को कुचल दिया

राहुल बोले- हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं क्यों?

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अनियमितताओं के आरोपों के चलते मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी-2026 को रद्द किए जाने के बाद मंगलवार को आरोप लगाया कि भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने 22 लाख छात्रों के सपनों को कुचल दिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तथाकथित अमृतकाल विषकाल बन गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला- पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का कहना था, हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। राहुल गांधी ने कहा, अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगी तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल, देश के लिए विषकाल बन गया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने नर्सिंग पेशे को मानवीय संवेदना की मिसाल बताया, कहा- डॉक्टर इलाज करते हैं, पर नर्से देती हैं नया जीवन

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नर्सिंग पेशे को मानवीय संवेदना की मिसाल बताते हुए कहा कि अस्पताल में मरीज का इलाज भले ही डॉक्टर करते हों लेकिन रोगी को नया जीवन नर्सों की देखभाल से मिलता है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार शाम लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल के अलग-अलग वार्डों में जाकर नर्सिंग कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने अस्पताल में कार्यरत विभिन्न राज्यों केरल, राजस्थान, पंजाब आदि नर्सिंग कर्मचारियों से विशेष तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के पीछे देश के कोने-कोने से आए इन जांबाज स्वास्थ्यकर्मियों- का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा, नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवीय संवेदना की मिसाल है। डॉक्टर यदि उपचार करते है तो नर्से अपनी ममता और देखभाल से मरीज को नया जीवन देती है। कठिन परिस्थितियों में आपका धैर्य हम सभी के लिए प्रेरणा है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बताया कि दिल्ली सरकार ने 27 साल के लंबे इंतजार के बाद नर्सिंग इंटर्न के मानदेय में 27 गुना की वृद्धि करते हुए इसे 13150 रुपये कर दिया है जो पहले मात्र 500 रुपये था। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार ने 1,388 नर्सिंग अधिकारियों और 41 पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति पत्र भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार स्वास्थ्यकर्मियों की कार्य संस्कृति को और बेहतर बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

खाली जुबानी खर्च करने से देश नहीं चलता- तेजस्वी यादव

नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है. मंगलवार (12 मई, 2026) को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कई सवाल उठाए हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक के कारण 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है. 23 लाख छात्रों के भविष्य से एक बार फिर खिलवाड़ किया गया. बिहार और देश में पेपर लीक का अंतहीन सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा, क्या भाजपा की सरकारों में इतनी भी प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, इच्छाशक्ति व कौशल नहीं है कि एक सामान्य परीक्षा को बिना पेपर लीक हुए सुनियोजित ढंग से आयोजित कर सके या फिर ये भी कोई संयोग और प्रयोग वाला दांव है जिससे देश की रुलाई में भी सत्ता को मलाई मिलती रहे. तेजस्वी ने कहा कि सत्ता संरक्षण में लगातार होते पेपर लीक से सरकार की नीति और नीयत पर ही सवाल उठ रहा है.

विपक्ष का नेता रबर स्टैम्प नहीं- राहुल ने सीबीआई प्रमुख की चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, पीएम पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश के अगले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक के चयन से जुड़ी अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और औपचारिक रूप से असहमति नोट भी सौंपा।

राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैम्प नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से समझौता नहीं कर सकते और किसी भी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर उसे वैधता नहीं दे सकते।

चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार सीबीआई का राजनीतिक उपयोग कर रही है, जिससे यह संस्था विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने का माध्यम बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी कारण चयन समिति में विपक्ष के नेता की भूमिका सुनिश्चित की गई थी, लेकिन उन्हें प्रभावी भागीदारी से वंचित किया जा रहा है।

जानकारी नहीं देने का आरोप

राहुल गांधी के अनुसार, उन्हें पात्र उम्मीदवारों की आवश्यक जानकारी जैसे सेल्फ-अप्रेजल रिपोर्ट और 360-डिग्री असेसमेंट उपलब्ध नहीं कराई गई।

उन्होंने कहा कि 69 उम्मीदवारों की फाइलें पहली बार बैठक के दौरान देखने को दी गईं, जिससे उनका सही मूल्यांकन संभव नहीं था। उन्होंने इसी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह कदम पहले से तय उम्मीदवार को चुनने की ओर इशारा करता है।

टॉप बॉस की दौड़ में शामिल जीपी सिंह

सीबीआई के नए निदेशक की दौड़ में कई आईपीएस अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है। इनमें एक आईपीएस तो ऐसे है, जिन्हें केंद्र सरकार के दो पावरफुल मंत्रियों का साथ मिल रहा है। अब देखना ये है कि पीएमओ किसके नाम को हरी झंडी देता है। इनमें पहला नाम सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह का है। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विश्वासपात्र हैं।

सीआरपीएफ में आने से पहले वे असम के डीजीपी रहे है। असम में उग्रवाद और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए माओवाद को समाप्त करने में उनका खास योगदान रहा है। जीपी सिंह, दो सप्ताह से भी अधिक समय तक पश्चिम बंगाल चुनाव में सड़कों पर उतरे रहे। बंगाल में निष्पक्ष और भय मुक्त मतदान के लिए उन्होंने दिन-रात अपने जवानों के साथ कड़ी मेहनत की है। अब उन्हें इसका इनाम मिल सकता है।

कब लगेगी नए निदेशक के नाम पर मुहर?

केंद्र सरकार ने पिछले साल सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया था। सीबीआई का नया निदेशक कौन होगा, इसके लिए हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें नए निदेशक के नाम पर मुहर लगेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत शर्मा शामिल हैं। प्रवीण सूद को 2023 में दो वर्ष के लिए सीबीआई चीफ बनाया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने सूद को सेवा विस्तार देकर उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। साल 2021 में केंद्र सरकार दो अध्यादेशों को मंजूरी देकर सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की अनुमति दी थी। इसके मुताबिक, दो साल का तय कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्हें एक-एक वर्ष के लिए तीन सेवा विस्तार दिए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल प्रवीण सूद को दूसरा सेवा विस्तार मिलने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं।

बीजेपी- ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम- राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग के चोर बाजार में जो जितनी बड़ी चोरी करेगा, उसे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया, भाजपा-निर्वाचन आयोग के चोर बाजार में - जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम। अग्रवाल को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले, पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग के विशेष पर्यवेक्षक रहे सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री अधिकारी का सलाहकार

उभरता आजमगढ़

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित जनपद आजमगढ़ वर्तमान में अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों के संरक्षण और आधुनिक पर्यटन विकास के युग की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों और जिला प्रशासन के कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप यह क्षेत्र अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। प्रदेश सरकार जनपद के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पुनर्जीवित कर रही है, साथ ही उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस कर एक सुव्यवस्थित पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की दिशा में पुख्ता प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। यह पहल न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने का एक माध्यम है, बल्कि यह ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी भी साबित होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य योजना के माध्यम से आजमगढ़ के पर्यटन ढांचे को मजबूती देने के लिए कुल 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनके लिए 13 करोड़ 19 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। इसमें से लगभग 5 करोड़ 95 लाख रुपये की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है, जिससे निर्माण कार्यों ने धरातल पर गति पकड़ ली है। प्रदेश सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि आस्था के केंद्रों को पर्यटन के आधुनिक मानकों के अनुरूप ढाला जाए ताकि दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अंतर्गत जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्थित प्राचीन और पौराणिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। सगड़ी क्षेत्र के मालटेपुर स्थित कैवल्य धाम शिव मंदिर के विकास के लिए स्वीकृत राशि का एक बड़ा हिस्सा जारी किया जा चुका है, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। इसी प्रकार, मुबारकपुर के ग्राम सभा डिलिया में प्राचीन हनुमान मंदिर और लालगंज के ग्राम ढेकवा स्थित ब्रह्मस्थान स्थल का विकास कार्य जिला प्रशासन की देखरेख में प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मात्र सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से उस स्थानीय संस्कृति और लोक विश्वास को संरक्षित करना है, जो सदियों से इस माटी की पहचान रहा है। नगर पंचायत अजमतगढ़ का प्राचीन हनुमान मंदिर हो या फूलपुर-पवई क्षेत्र का पौराणिक दुर्वासा ऋषि आश्रम, प्रत्येक स्थल के लिए योजनाबद्ध तरीके से निवेश किया जा रहा है ताकि यहाँ की ऐतिहासिक महत्ता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया जा सके। आजमगढ़ के इस समग्र विकास अभियान में ईको-टूरिज्म को एक नई और अभिनव दिशा दी गई है। सदर क्षेत्र के अंतर्गत सिलनी स्थित चन्द्रमा ऋषि आश्रम के समग्र विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना आजमगढ़ को एक शांत, प्राकृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। ईको-टूरिज्म के इस मॉडल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक पर्यटन के बीच एक अनूठा संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन का मानना है कि प्रकृति के सानिध्य में स्थित इन ऋषि आश्रमों का विकास न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करेगा। इसी क्रम में सदर क्षेत्र के एकलव्य स्थल एवं भगवान शंकर जी के स्थान और निजामाबाद के प्रसिद्ध दत्तात्रेय आश्रम के लिए भी धनराशि आवंटित कर निर्माण कार्यों को तेज कर दिया गया है। इन स्थलों के विकास से आजमगढ़ के ऐतिहासिक गौरव में वृद्धि होगी और यह प्रदेश के चुनिंदा पर्यटन स्थलों की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। जनपद के फूलपुर-पवई क्षेत्र के गढ़वा हनुमान मंदिर जैसी बड़ी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ 135.63 लाख रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे को सुधारा जा रहा है। इसके साथ ही दीदारगंज के बंधवा महादेव पातालपुरी मंदिर और गोपालपुर के तेनबर बाबा मंदिर का विकास भी इसी विस्तृत कार्ययोजना का हिस्सा है। इन सभी कार्यों के संपादन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सौंपी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निर्माण कार्यों में उच्च स्तर की गुणवत्ता बनी रहे। जिला प्रशासन इन परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता की निरंतर समीक्षा कर रहा है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन स्थलों को जनता को समर्पित किया जा सके। सरकार का मानना है कि 'आस्था के साथ विकास' की इस अवधारणा से न केवल सांस्कृतिक गौरव वापस लौटेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पर्यटन के इस विस्तार का सीधा और सकारात्मक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना सुनिश्चित है। जैसे-जैसे इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आजमगढ़ की पारंपरिक कलाओं और यहाँ के स्थानीय उत्पादों को पर्यटन केंद्रों के माध्यम से एक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार की यह नीति पर्यटन को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे आर्थिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बनाने की है। आधारभूत ढांचे जैसे सड़क, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होने से पर्यटकों को अपने प्रवास के दौरान सुविधाओं का अहसास होगा। क्षेत्र में निजी निवेश की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। आजमगढ़ का यह बदलता स्वरूप आने वाले समय में नवीन आकर्षणों के साथ नए पर्यटकीय क्षेत्र का केन्द्र बनेगा। धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन का यह एकीकृत ढांचा आजमगढ़ को उसकी नई पहचान दिलाने के लिए तैयार है। सरकार की योजनाओं का कुशल क्रियान्वयन और जिला प्रशासन की सक्रियता ने उन प्राचीन धरोहरों को मुख्यधारा में ला खड़ा किया है, जो लंबे समय से उपेक्षित थीं। अब आजमगढ़ केवल अपनी प्राचीन गाथाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने आधुनिक पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सुव्यवस्थित तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाएगा। आने वाले वर्षों में जब ये सभी ग्यारह परियोजनाएं और ईको-टूरिज्म का विशेष प्रोजेक्ट पूर्णता की ओर बढ़ेगा, तब आजमगढ़ का पर्यटन मानचित्र पूरी तरह से बदल चुका होगा। आस्था, अध्यात्म और प्रकृति के अद्भुत संगम के रूप में यह जनपद अब एक नए और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर है, जहाँ विकास की रोशनी प्राचीनतम मंदिर की दीवारों और आधुनिक पर्यटक सुविधाओं, दोनों पर समान रूप से चमक रही है।

शाह के दांव से ममता चारों खाने चित्त

पिछले तीन-चार महीनों में मैं जितने भी गैरभाजपाई नेताओं से मिला, सब यह कह रहे थे कि दीदी यानी ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है। वो साम, दाम, दंड, भेद में माहिर हैं, बंगाल की नब्ज उनके कब्जे में है। यहां तक कि कुछ भाजपा नेता भी दबे स्वर में कह रहे थे कि शायद दीदी जीत जाएंगी। मगर मेरा आंकलन था कि अमित शाह के चक्रव्यूह को तोड़ना ममता के लिए आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में रोड शो करके लौटे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुझसे कहा था कि भाजपा यदि 200 से ज्यादा सीटों पर जीते तो आश्चर्य मत कीजिएगा। कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ परिचितों से मेरी लगातार बातचीत हो रही थी और सबका यही कहना था कि यदि तृणमूल कांग्रेस की दबंगई पर लगाम लग गई तो फिर भाजपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता और अंततः यही हुआ। अमित भाई शाह ने ऐसी नकेल कसी कि तृणमूल के दबंग दड़बे से बाहर ही नहीं निकल पाए। केंद्रीय पुलिस बलों के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात थे ताकि कोई किसी को वोट देने से नहीं रोक सके। इस बार चुनाव आयोग ने देशभर से जांबाज अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक बना कर वहां भेजा। चुनाव पर्यवेक्षक बन कर पश्चिम बंगाल पहुंचे यूपी के जांबाज डीआईजी अजय पाल शर्मा का वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा कि किस तरह से वे जहांगीर नाम के एक प्रत्याशी के मोहल्ले में पहुंच कर चेतावनी दे रहे हैं कि फिर किसी को धमकाने की सूचना मिली तो खैर नहीं। जहांगीर वो शख्स है जिसके लोग मतदाताओं को धमका रहे थे कि भाजपा को वोट दिया तो टुकड़े कर देंगे। फलता विधानसभा क्षेत्र में जहांगीर का सिक्का चलता है, वह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का बहुत करीबी है। मगर अजय पाल शर्मा वो शख्स है जिनके नाम से ही अपराधी कांपते हैं। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। भयमुक्त चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तो सजग था ही, अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत और निडरता भर दी थी कि वे दबंगों का मुकाबला करने को तैयार थे। शाह पूरे 15 दिन पश्चिम बंगाल में रहे और हर जोन में उन्होंने रात्रि प्रवास किया। रात 12 बजे के बाद तक वे बैठकें ले रहे थे। उनका लक्ष्य बहुत साफ था कि मतदान के दिन सुबह 11 बजे तक भाजपा के सारे वोट सौ फीसदी पड़ जाएं। एसआईआर में लगभग 91 लाख अवैध मतदाताओं के नाम कट जाने से ममता की कमर पहले ही टूट चुकी थी। शाह की व्यूह रचना ने उन्हें धराशायी कर दिया। ममता फाइटर हैं लेकिन इस बार शेर को सवा शेर मिल गया। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अमित शाह ने 50 से ज्यादा सभाएं और रोड शो किए। उनकी कुछ घोषणाओं ने तो जनता का दिल ही जीत लिया। उन्होंने कहा कि गुंडे घर से बाहर न आएं वरना गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। उन्होंने हुंकार भरी कि बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाजपा सरकार बनते ही भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए 45 दिनों के भीतर जमीन दे देंगे। सीमा पर फेंसिंग के लिए ममता सरकार जमीन नहीं दे रही थी। खुली सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में घुसते हैं। ममता पर आरोप है कि घुसपैठिए, उनके तंत्र की मदद से भारतीय नागरिक में परिवर्तित हो रहे हैं। बदले में वो टीएमसी को वोट देते रहे हैं। इधर अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं का ऐसा संयोजन किया कि सभी प्रमुख क्षेत्रों में लोग उन्हें सुन पाएं। प्रधानमंत्री ने 19 जिलों में 24 स्थानों पर सभाएं कीं, रोड शो किए, उन्होंने ढाई सौ से ज्यादा सीटों को कवर किया। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस विजय के असली हकदार अमित भाई शाह हैं। अमित शाह ने 2014 में घोषणा की थी कि ममता बनर्जी की सरकार को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। बारह साल जरूर लगे लेकिन उन्होंने जो ठाना था, उसे कर दिखाया। 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल तीन सीटें मिली थीं। 2021 में यह संख्या बढ़कर 77 तक पहुंच गई थी. और 2026 में आंकड़ा 207 पर आ पहुंचा है, वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को अमित शाह ने पूरा कर दिखाया। हार के बाद ममता ने कहा है कि उनकी 100 सीटें भाजपा ने लूट ली हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये वोट चोरी है, मैं कम से कम पचास सालों से तो राजनीति को बहुत करीब से देख ही रहा हूं। हारने वाले पहले भी कोई न कोई बहाना ढूंढते थे ताकि खुद की लाज बचाई जा सके मगर इस बात का विश्लेषण करते थे कि वे क्यों हारे? अब विश्लेषण नहीं होता बल्कि केवल आरोप लगाए जाते हैं। कोई समझने को तैयार नहीं है कि केवल कोसने से पहलवान कमजोर नहीं होता। पहलवान को हराना है तो खुद को बुलंद करना होगा और जरूरी दांव-पेंच भी सीखने होंगे और ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रहित से समझौता न हो। अन्यथा वही परिणाम आएगा जो पश्चिम बंगाल में आया है। लोगों को मैंने कहते सुना है कि पश्चिम बंगाल को अमित शाह ने बचा लिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी वाकई कमाल की है। एक जगह जीतती है तो ठहरती नहीं, अगली जीत के लक्ष्य लेकर आगे बढ़ जाती है। कहीं हारती है तो अगले चुनाव में विजय का नया लक्ष्य लेकर काम में लग जाती है। यह जोड़ी 24 बाय 7 काम करती है। विपक्ष के पास क्या ऐसी कोई जोड़ी है? विपक्ष को कौन समझाए कि जुबानी जमा खर्च और आरोपों की फेहरिस्त से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए रातों की नींद खराब करनी होती है। फिर फैलता है उजाला। तमिलनाडु में विजय की जीत का उजाला क्यों फैला? क्योंकि द्रविड़ राजनीति से अलग हटकर विजय ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नया स्वरूप पेश किया। जन आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया। भाजपा असम में तीसरी बार क्यों जीती? क्योंकि जो कहा, उसे पूरा किया।

वामपंथ का आखिरी गढ़ केरल में क्यों ढह गया? क्योंकि भारतीय वामपंथियों की तासीर रही है कि बीजिंग या मास्को में बारिश हो जाए तो हिंदुस्तान में छाता खोल लें। आशय यह है कि जनता के दिल में जगह बनानी है तो जनता की नब्ज को पहचानना होगा।

सम्पादकीय...

भाई कन्हैया के गांव में

पंजाब में माहौल एक बार फिर जहरीला हो चला है। ऐसे माहौल में एक महान पंजाबी महानायक को याद कर लेना चाहिए। एक बार पंजाब सरकार के आग्रह पर हरियाणा में भी भाई कन्हैया की जन्म-त्रिशताब्दी मनाने की बात चली। विचाराधीन विषय था, 'भाई कन्हैया' की त्रिशताब्दी।' पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री को औपचारिक पत्र भेजा गया जिसमें आग्रह किया गया था कि चूंकि पंजाब व हरियाणा की विरासत सांझी है इसलिए भाई कन्हैया की त्रिशताब्दी हरियाणा में भी पूरे जोश व श्रद्धा के साथ मनाई जाए। इसके लिए हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक विशेष बैठक बुलाई। बैठक में एक प्रश्नात्मक सुझाव आया, 'क्या हम इसकी शुरुआत भाई कन्हैया की जन्मस्थली से कर सकते हैं?' इस पर मुख्यमंत्री ने बात आगे बढ़ाई, 'इस योजना का रोडमैप क्या होगा?' मुख्यमंत्री के एक अधिकारी अपनी कल्पनाशीलता के कारण अपना होमवर्क कर चुके थे। सुझाव आया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक 51 सदस्यीय शिष्टमण्डल भाई कन्हैया के जन्म-गांव जाएगा। वहां से पवित्र जल कलशों में भर कर एक शोभायात्रा निकाली गई। तब मुख्यमंत्री ने बैठक में ही कह दिया था कि 'शिष्टमण्डल में कुछ पढ़े-लिखे विद्वान भी ले लो, कहीं ज्यादातर मेरे जैसे मोलड़ ही न हों।' एक सुझाव आया कि इस दल में पंडित जसराज, जिनका जन्म जिला हिसार के एक गांव में हुआ था और इसी तरह के कुछ विद्वानों व अदीबों को भी ले जा सकते हैं। सूची बनी। उसमें केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष प्रो. सतिंदर सिंह नूर जो कि मूल रूप से अम्बाला के थे, नाटककार डॉ. आत्मजीत, मैं स्वयं और पत्रकारों के वर्ग में इंडियन एक्सप्रेस के विपिन पब्बी, कंवर संधू, अजीत समूह के बरजिंदर सिंह हमदर्द व पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल व हरियाणा के कुछ मंत्री, विधायकों को भी लिया गया। मुख्य सूत्रधार तत्कालीन लोकसंपर्क निदेशक श्री राजेश खुल्लर थे। एक अन्य अधिकारी धनपत सिंह भी शामिल थे। इस यात्रा के मध्य एक दुखद घटना यह भी थी जबकि वरिष्ठ पत्रकार कंवर संधू को वहां से वापिस भेजा गया क्योंकि पाक एजेंसियों की नजर में वह 'अवांछित' पत्रकारों की सूची में थे। सभी उदास थे। पहले तो विरोध स्वरूप यात्रा को वहीं छोड़ने का मन बना, मगर बाद में कंवर ने स्वयं ही सबसे आग्रह किया कि यात्रा जिस पवित्र लक्ष्य के लिए है, उसे स्थगित नहीं किया जाए। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए लोकसंपर्क निदेशक ने ही पहलकदमी की। उन्होंने वहां के निदेशक लोक सम्पर्क से फोन पर बातचीत की। वहां के मुख्यमंत्री से हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात कराई। पाक-पंजाब के मुख्यमंत्री ने सहर्ष अपनी ओर से औपचारिक निमंत्रण भेजा, जिसके आधार पर वीजा आदि की कार्यवाही हुई। विदेश मंत्रालय से भी स्वीकृति मिल गई। इसी बीच तय यह भी हुआ कि शिष्टमण्डल ननकाना साहब भी जाएगा, वारिस शाह की मजार पर भी चादरें चढ़ाई जाएंगी और लौटने से पहले सर छोटूराम के लाहौर स्थित पुराने आवास से भी कुछ स्मृति चिह्न लाने का प्रयास भी किया जाएगा। लाहौर में यह शिष्टमण्डल तीन दिन तक छाया रहा।

वैश्विक संकट के बीच सबसे बड़े कूटनीतिक मिशन पर निकल रहे हैं मोदी, विश्व राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर

आर्कटिक क्षेत्र, हरित जहाजरानी और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में दोनों देशों का सहयोग भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष होगा। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के शीर्ष नेता शामिल होंगे। यह मंच भारत और नॉर्डिक देशों के बीच प्रौद्योगिकी, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, सतत विकास और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई रणनीतिक दिशा देगा। वैश्विक आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाने और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में यह सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला के साथ उनकी बैठकें भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगी। दोनों देश 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग इसके प्रमुख क्षेत्र हैं।

वैश्विक चुनौतियों, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, ऊर्जा संकट, आपूर्ति शृंखला की अनिश्चितताओं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़े कूटनीतिक मिशन पर निकल रहे हैं। 15 मई से 20 मई तक प्रस्तावित उनकी बहुराष्ट्रीय विदेश यात्रा के दौरान वह संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। यह यात्रा भारत की वैश्विक रणनीति, आर्थिक हितों और सामरिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस दौरान ऊर्जा सहयोग, व्यापार, हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा, निवेश, नवाचार और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका और अधिक मजबूत होने की संभावना है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारत अपने पारंपरिक मित्र देशों के साथ केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति शृंखला जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को भी विस्तार देना चाहता है। हाल के वर्षों में भारत ने विश्व मंच पर एक भरोसेमंद और संतुलित शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि यूरोप और पश्चिम एशिया के देश भारत को भविष्य के आर्थिक और सामरिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे, जहां वह राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग, निवेश, डिजिटल भुगतान, रक्षा और भारतीय समुदाय के कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा बीते पच्चीस वर्षों में भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते ने व्यापार को नई गति दी है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी संयुक्त अरब अमीरात भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके अलावा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा दोनों देशों की सामरिक निकटता को और अधिक मजबूत बना रहा है। वहां रह रहे लाखों भारतीय दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की मजबूत कड़ी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे। वह यात्रा भारत और नीदरलैंड के बीच बढ़ते आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग को नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री वहां के राजा विलेम अलेक्जेंडर, महारानी मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रोब येटन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, जल प्रबंधन, सेमीकंडक्टर और नवाचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। नीदरलैंड यूरोप में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत में बड़े निवेशकों में शामिल है। जल प्रबंधन और कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नीदरलैंड की विशेषज्ञता भारत के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। दोनों देश मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में भी एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। मोदी की स्वीडन की यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के साथ बढ़ते सहयोग को और मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, हरित परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की संभावनाएं हैं। हम आपको बता दें कि स्वीडन की अनेक प्रमुख कंपनियां भारत में सक्रिय हैं और दोनों देशों के बीच नवाचार आधारित साझेदारी तेजी से विकसित हो रही है। भारत और स्वीडन लोकतांत्रिक मूल्यों, सतत विकास और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में समान सोच रखते हैं।

हरित औद्योगिक परिवर्तन और जलवायु संरक्षण के लिए दोनों देशों का सहयोग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद नॉर्वे जाएंगे, जहां वह तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी और पिछले तैंतालीस वर्षों में भारत से वहां होने वाली पहली प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा भी मानी जा रही है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के साथ होने वाली वार्ता में व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी और समुद्री अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर रहेगा। भारत और नॉर्वे के संबंध समुद्री सहयोग, हरित ऊर्जा और सतत विकास पर आधारित हैं। भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की संभावना है। नॉर्वे का विशाल पेंशन कोष भारतीय पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण निवेश कर चुका है। आर्कटिक क्षेत्र, हरित जहाजरानी और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में दोनों देशों का सहयोग भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष होगा। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के शीर्ष नेता शामिल होंगे। यह मंच भारत और नॉर्डिक देशों के बीच प्रौद्योगिकी, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, सतत विकास और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई रणनीतिक दिशा देगा। वैश्विक आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाने और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में यह सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला के साथ उनकी बैठकें भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगी। दोनों देश 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इटली ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से अलग होकर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है, जिससे दोनों देशों की सामरिक निकटता बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में सह-विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया जा रहा है। इटली भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयासों का भी समर्थन करता रहा है। वहां रह रहा भारतीय समुदाय दोनों देशों के संबंधों को सामाजिक और सांस्कृतिक मजबूती प्रदान करता है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विदेश यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का प्रतीक भी है। यह यात्रा भारत को ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग, हरित विकास, रक्षा साझेदारी और वैश्विक व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगी। साथ ही यह संदेश भी देगी कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख और विश्वसनीय केंद्र बनकर उभर रहा है।

सखी कार्यक्रम से बदलता उत्तर प्रदेश का सामाजिक आर्थिक

इस योजना के तहत कार्य कर रही महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी उनका सम्मान बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर, सुल्तानपुर की प्रियंका मौर्य और लखनऊ की अनीता पाल जैसी बीसी सखियाँ प्रतिमाह औसतन 45,000 रुपये से अधिक का कमीशन अर्जित कर रही हैं। यह आय उनके परिवार के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही, ये महिलाएं अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक बीसी सखियों ने 121 करोड़ रुपये से अधिक का कमीशन अर्जित किया है, जो यह दर्शाता है कि यह योजना महिलाओं के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक आजीविका का माध्यम बन चुकी है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, जिनमें बीसी सखी कार्यक्रम एक अत्यंत प्रभावशाली और दूरगामी पहल के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित यह कार्यक्रम न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को भी अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ कर रहा है। एक ग्राम पंचायत-एक बीसी सखी के सिद्धांत पर आधारित यह योजना आज लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।

बी.सी. सखी कार्यक्रम: अवधारणा और उद्देश्य: -

बी.सी. सखी (ठनेपदमे ब्वततमेचवदकमदज ेंीप) कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सेवाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनके ही गांव में बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये सखियाँ ग्रामीण समुदाय को उनके घर के निकट ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, जिससे लोगों को बैंक शाखाओं तक जाने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाती हैइस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह महिलाओं को केवल रोजगार ही नहीं देता, बल्कि उन्हें डिजिटल और वित्तीय साक्षरता से भी सशक्त बनाता है। इससे महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि समाज में अपनी एक अलग पहचान भी स्थापित करती हैं।

वित्तीय समावेशन की दिशा में क्रांतिकारी कदम: -

बीसी सखी कार्यक्रम ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को नई गति प्रदान की है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 40,000 बीसी सखियाँ सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जो गांवों में घर-घर जाकर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इनके माध्यम से अब तक 44,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेन-देन किए जा चुके हैं, जो इस योजना की सफलता का स्पष्ट प्रमाण हैये सखियाँ नकद जमा और निकासी, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (।म्च्ै) के माध्यम से लेन-देन, बैलेंस जांच, बीमा, पेंशन, और ऋण पुनर्भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा, वे विभिन्न सरकारी योजनाओं में नामांकन भी सुनिश्चित करती हैं, जिससे ग्रामीणों को सरकारी लाभ समय पर मिल सके। इस पहल ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाया है, जहां बैंकिंग सुविधाएं पहले बहुत सीमित थीं। अब ग्रामीणों को छोटी-छोटी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है।

महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम: -

बीसी सखी कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इस योजना के तहत कार्य कर रही महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी उनका सम्मान बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर, सुल्तानपुर की प्रियंका मौर्य और लखनऊ की अनीता पाल जैसी बीसी सखियाँ प्रतिमाह औसतन 45,000 रुपये से अधिक का कमीशन अर्जित कर रही हैं। यह आय उनके परिवार के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही, ये महिलाएं अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक बीसी सखियों ने 121 करोड़ रुपये से अधिक का कमीशन अर्जित किया है, जो यह दर्शाता है कि यह योजना महिलाओं के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक आजीविका का माध्यम बन चुकी है।

बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और तकनीकी सशक्तिकरण: -

बीसी सखी कार्यक्रम के तहत कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (च्ेन् ठंदो) साझेदार के रूप में जुड़े हुए हैं। इन बैंकों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य बैंक इस पहल में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही, बीसी सखियों को डिजिटल उपकरणों जैसे माइक्रो एटीएम, लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस करने पर विचार चल रहा है। बैंकों के सी एस आर फंड के माध्यम से इन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना है, जिससे वे अपने कार्य को और अधिक कुशलता से कर सकें।डिजिटल माध्यमों के उपयोग से न केवल सेवाओं की गति बढ़ी है, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। इससे ग्रामीणों में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वास भी बढ़ा है।

सेवाओं का विस्तार और नई संभावनाएं: -

बीसी सखी कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके कार्यक्षेत्र का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अब बीसी सखियों को जन सुविधा केंद्रों के संचालन, बीमा सेवाओं, आरडी खाता खुलवाने, ऋण वितरण, ऋण वसूली, और पोस्ट ऑफिस की योजनाओं से जोड़ने जैसे कार्यों में योगदान लेने का मसौदा बन रहा है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में बीसी सखियों को आधार अपडेट जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी शामिल करने पर विभाग मे विचार मंथन चल रहा है। इससे उनकी भूमिका और अधिक व्यापक हो जाएगी और उन्हें अतिरिक्त आय के अवसर भी प्राप्त होंगे।बड़ी ग्राम पंचायतों में एक से अधिक बीसी सखियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को और बेहतर बनाया जा सके।

जनपदों की उपलब्धियां और प्रतिस्पर्धा: -

बीसी सखी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में विभिन्न जनपदों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रही है। वर्तमान में प्रयागराज इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर है, जबकि बरेली और शाहजहांपुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यह प्रतिस्पर्धा न केवल कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन को प्रेरित करती है, बल्कि अन्य जनपदों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करती है।

समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल: -

बीसी सखी कार्यक्रम केवल एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत में समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम बन चुका है।

यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रही है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां एक ओर महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका मिल रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही आवश्यक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में भी मदद मिल रही है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कन्हा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, लाल पैन्सलिवना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/...)

श्रमिकों तक पहुंचे सरकार की योजनाओं का लाभः कमिश्नर

मुरादाबाद।

मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मण्डल स्तरीय श्रम बन्धु समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुँचाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास के लिये प्रतिबद्ध है, इसके लिए आवश्यक है कि श्रमिक हितों का ध्यान रखा जाये तथा उद्योगों के विकास के लिये उपयुक्त माहौल तैयार किया जाये। सम्बन्धित विभाग उद्योगों के विकास के लिए सहयोगी के रूप में काम करें। ईपीएफ, ईएसआई, श्रम विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिले तथा श्रमिकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो इसके लिये विभाग पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें। मंडलायुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि लेबर अड्डों पर काम के लिए आने वाले श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान किये जाने के लिए मुरादाबाद में लेबर अड्डों का विकास करें। जहां बैठने की सुविधा हो तथा छाया व स्व'छ पीने का पानी भी उपलब्ध हो। उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंडलायुक्त के समक्ष उद्योगों की ईपीएफ व ईएसआई से सम्बन्धित समस्याएं रखी, जिसे

तत्काल निराकरण कराने के निर्देश सम्बन्धित विभागों को दिए। श्रमिकों का पक्ष रखते हुए ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि ने श्रमिकों को ईएसआई द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलने में आने वाली समस्याओं जैसे- श्रमिकों का ईलाज की समस्या अधिक बारे में बताया। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आयुक्त ने ईएसआई विभाग को निर्देशित किया। उप श्रम आयुक्त ने शासन द्वारा जारी नवीन वेतन दरों के विषय में सभी को अवगत कराया तथा इसे दिनांक 01 अप्रैल 2026 से लागू किये जाने के संबंध में अवगत कराया, जिससे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नवीन दरों के अनुसार मिल सके। आयुक्त ने सभी उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों व सेवायोजकों को निर्देश दिये कि शासन द्वारा जारी नवीन वेतन दरों के अनुसार सभी कारखाना स्वामी व सेवायोजक श्रमिकों को वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें। बैठक में आयुक्त ने श्रम विभाग द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय के वर्ष 2026 में कक्षा-10 में शीर्ष स्थान प्राप्त 05 विद्यार्थियों- उदय प्रताप 95 प्रतिशत, पार्थ कुमार 92.2 प्रतिशत, कु0 लक्षिता 90.4 प्रतिशत, अंकित 89 प्रतिशत एवं सिद्धान्त 88.2 प्रतिशत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बैठक में अपर आयुक्त अरूण कुमार सिंह, उप आयुक्त विकास गजेन्द्र सिंह, अपर नगर आयुक्त मुरादाबाद, उप निदेशक कारखाना, मुरादाबाद, सहायक निदेशक कारखाना मुरादाबाद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से ब्रांच मैनेजर, कर्मचारी भविष्य निधि से प्रवर्तन अधिकारी एवं सम्बन्धित विभागों के मण्डल के सभी जनपदों के समिति के सदस्य, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि तथा ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कुन्डलपुर की तीर्थ यात्रा को 150 श्रद्धालुओं का टीएमयू कैंपस से प्रस्थान

मुरादाबाद।

भगवान महावीर जंयती महोत्सव समिति, मुरादाबाद एवम् मुख्य आयोजक मनीष जैन (गंज), पंकज जैन द्वारा 150 श्रद्धालुओं को मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित श्री बड़े बाबा कुन्डलपुर की तीर्थ यात्रा आयोजन किया। इस तीर्थ यात्रा को मुरादाबाद के डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बतौर मुख्य अतिथि, 'वाइट मजिस्ट्रेट शक्ति दुबे एवम् टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन, जीवीसी मनीष जैन, एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए बसों को रवाना किया। तीर्थ यात्रा बस से दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहां से ऊर्जाधानी एक्सप्रेस से दमोह पहुंच कर श्री बड़े बाबा का आशीर्वाद लेगी। श्री 1008 आदिनाथ भगवान बड़े बाबा कुन्डलपुर की प्रतिमा 2,000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, जिसका नव्य और भव्य निर्माण आचार्यश्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में कुछ वर्ष पूर्व कराया गया था। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा, तीर्थ यात्रा के समय धाम यानी तीर्थ स्थान, धामी यानी पू'य भगवान, धामवासी यानी तीर्थ स्थान पर रहने वाले लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस मौके पर फर्स्ट लेडी वीना जैन, ऋचा जैन, जाह्नवी जैन, मुरादाबाद जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन आदि की गरिमामयी मौजूदगी रही। सभी श्रद्धालुओं का ढोल बजाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं के अल्पाहार की व्यवस्था एवम् कार्यक्रम का आयोजन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के तीर्थंकर महावीर जिनालय समिति की ओर से की गई। यात्रा प्रस्थान के समय संदीप जैन, नीलम जैन, उषा जैन, जयरानी जैन, राजेन्द्र जैन आदि मौजूद रहे।

'गुरु की शिक्षा एवं सान्निध्य से ही मनुष्य का उद्धार सम्भव'

117 वां भंडारा संपन्न

मुरादाबाद।

स्वामी नारदानन्द ऋषि आश्रम में आज 117 वां भंडारा आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर आश्रम के अध्यक्ष एवं प्रखर वक्ता बाबा संजीव आकांक्षी ने कहा कि गुरु का सानिध्य एवं गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा, गुरु के दिए गए निर्देश और गुरु की कृपा से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। कोई भी साधारण मनुष्य जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए एवं अपने भौतिक जीवन को सफल बनाने के लिए यदि गुरु का सानिध्य पकड़ ले और स'चे गुरु की सेवा में लग जाए तो जहां एक ओर वह अपेक्षित सफलताएं प्राप्त करता है वहीं दूसरी ओर उसका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होकर जीवन सफल होने लगता है। स्वयं परमात्मा भी मानव जीवन में आकर गुरु का सानिध्य और गुरु की शरण के बिना जीवन में सफल नहीं हो पाए। भगवान कृष्ण को भी संदीपनी गुरु की शरण में जाकर उनके गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी, वहीं गुरु के आश्रम में ही उनके परम मित्र सुदामा से उनकी भेंट एवं मित्रता हुई थी। ऐसे ही भगवान राम ने प्रारंभिक शिक्षा अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से प्राप्त करने के बाद शस्त्र और शास्त्र की विद्या गुरु विश्वामित्र से सीखी. दिव्य अस्त्रों का प्रयोग, उनकी साधना और विभिन्न मंत्रों के माध्यम से दिव्य अस्त्रों को प्रकट करने की शक्ति और समर्थ गुरु विश्वामित्र से ही उन्हें प्राप्त हुई। ऐसे दृष्टांतों से यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का रहना कितना महत्वपूर्ण है. व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े पद पर एवं कितना भी धन संपन्न हो जाए गुरु की कृपा के बिना जीवन में उद्धार और कल्याण संभव नहीं है। बाबा संजीव आकांक्षी ने कहा की स्वामी नारदानंद ऋषि आश्रम भी आदि जगदाचार्य की तपोस्थली रहा है। मंगल चिंतन के उपरांत भंडारे का आयोजन हुआ 117 में भंडारे का प्रसाद वितरण में प्रमुख रूप से प्रमोद रस्तोगी, पंकज शर्मा सुरेंद्र सिंह, मोहित अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, अमित कृष्णात्रेय, राखी शर्मा, प्रेमनाथ यादव, सुरेंद्र सिंह, उषा शर्मा, डॉ मनदीप सिंह, पुरुषोत्तम शर्मा, डॉली शर्मा, अमित कुमार, डॉक्टर सत्यवीर सिंह चौहान, विनय चौधरी आदि उपस्थित रहे।

एमआईसी में आयोजित हुआ विशेष जागरुकता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी जानकारी

फतेहपुर।ज

नपद न्यायाधीय/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलाश गांगुली द्वारा मुस्लिम इण्टर कालेज फतेहपुर में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

सचिव पलाश गांगुली ने कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए कहा कि आपसी, विवाद को कम करने के लिए संबधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित सुलह समझौता केन्द्र का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते है। प्रत्येक तहसील स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा पराविधिक स्वयं सेवको की तैनाती आम जनमानस को सुलभ न्याय प्रदान किये जाने हेतु की गई है। पूर्व में सचिव पलाश गांगुली को कालेज के प्रधानाचार्य डा0 रफीक अहमद ने बुके व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन पराविधिक स्वयं सेवक शेखर, रामेन्द श्रीवास्तव व अवधेश द्वारा किया। कार्यक्रम में विद्यार्थी एवं स्टाफ मौजूद रहा।

विकास भवन सभागार में ई-लाटरी के माध्यम से कृषकों का हुआ चयन

निःशुल्क उर्द, मूंग बीज मिनीकिट के साथ प्राप्त होगा संकर धान व ढेचा बीज

फतेहपुर। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना की अध्यक्षता में ई-लाटरी का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में खरीफ-2026 के अन्तर्गत निःशुल्क उर्द, मूंग बीज मिनीकिट एवं निर्धारित अनुदान की दर पर संकर धान बीज, ढेचा, बीज प्राप्त करने हेतु ई-लाटरी के माध्यम से कृषकों का चयन हुआ। जिसका मैसेज कृषि निदेशालय द्वारा कृषक के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दिये गये है। चयनित किसानों से अनुरोध किया गया है कि अपने विकास खण्ड में स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डार पर आधार कार्ड एवं खतौनी की छायाप्रति लेकर यथाशीघ्र पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से चयनित बीज प्राप्त कर लें।

94.72 लाख की लागत से बनेगा भव्य कल्प सरोवर, एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय ने किया शिलान्यास

अम्बेडकरनगर। नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के वासुदेवनगर वार्ड में सोमवार को नगर पंचायत निधि से 94 लाख 72 हजार रुपये की लागत से निर्मित होने वाले भव्य कल्प सरोवर का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय एवं नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित यह कल्प सरोवर वासुदेवनगर वार्ड में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समीप स्थित पक्के पोखरे को विकसित कर तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. हरिओम पांडेय ने कहा कि जहां-जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां निरंतर विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता के नेतृत्व में किछौछा क्षेत्र में लगातार जनहित एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे नगर पंचायत क्षेत्र को भव्य एवं दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने बताया कि उक्त पोखरे का विकास स्वर्गीय वासुदेव साहू की स्मृति में क्षेत्रीय जनता की मांग पर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसकी भव्यता आकर्षण का केंद्र बनेगी। साथ ही नगर पंचायत द्वारा अवैध कब्जों को हटवाकर जनसरोकार से जुड़े निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी संजय जैसवार, वरिष्ठ भाजपा नेता राम प्रकाश यादव, सभासद सुभाष निषाद, रामसागर निषाद, रोशन लाल निषाद, राम आधार यादव राजभर, मया राम, मास्टर प्रदीप कुमार, रुद्र प्रसाद उपाध्याय, महेंद्र जायसवाल, साहिल सोनी सहित बड़ी संख्या में सभासद, नगर पंचायत कर्मी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

भारत-नेपाल सीमा पर चिन्हित अवैध कब्ज़ों को हटाने की कार्यवाही में तेजी लाये- डीएम

अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध होगी कार्रवाई

बहराइच।

भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 0 से 15 किमी. में सरकारी भूमि एवं नो मेन्स लैन्ड पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रट सभागार में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। उप जिलाधिकारी नानपारा द्वारा अवगत गया कि तहसील नानपारा अन्तर्गत नो मैन्स लैण्ड पर 01 अतिक्रमण है, जो कि जीर्ण-शीर्ण मंदिर के रूप में है। उन्होंने बताया कि उक्त मंदिर में प्रतिस्थापित हेतु अन्य मंदिर का निर्माण करा दिया गया है। डीएम ने एसडीएम नानपारा को निर्देश दिया कि एसएसबी एवं अन्य संबंधित ग्रामवासियों से वार्ता करते हुये अग्रिम 15 दिवस में नियमानुसार नो-मेन्स लैण्ड पर स्थित अतिक्रमण को हटवा दिया जाय। बैठक में बताया गया कि भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 0 से 15 कि.मी. में सरकारी भूमि पर कुल 366 अवैध अतिक्रमण पाये गये, जिसमें से 219 अतिक्रमण को हटा दिया गया। वर्तमान में 147 अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अवशेष है। अवशेष 147 अवैध अतिक्रमण में से 113 पर वाद पंजीकृत है तथा 34 प्रकरण (31-स्थायी व 03 अस्थायी) में वाद पंजीकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में एसडीएम व तहसीलदार नानपारा को निर्देश दिया गया कि 31 प्रकरण, जो स्थायी प्रकृति के अवैध अतिक्रमणों में सम्बन्धित अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वाद पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें। एसडीएम नानपारा ने बताया कि वाद पंजीकृत 113 प्रकरणों में से 56 प्रकरणों में बेदखली का आदेश पारित हो चुका है, 39 प्रकरणों में बाजदायर प्राप्त हुआ है तथा 18 प्रकरण न्यायालय अपर सिविल जज बहराइच पर विचाराधीन है। एसडीएम ने बताया कि 56 प्रकरण जिनमें बेदखली का आदेश पारित हुआ है उनमें से 46 प्रकरण ऐसे है जिनमें प्रभावित व्यक्ति के पास दूसरा मकान नहीं है या भूमिहीन है तथा 09 प्रकरणों में अन्य मकान या भूमि है तथा एक स्थान पर मलंगशाह मजार बनी हुयी है। डीएम द्वारा एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश दिया गया कि 46 प्रकरणों, जिनमें प्रभावित व्यक्ति के पास दूसरा मकान नहीं है या भूमिहीन हैं, को चिन्हित करते हुये नियमानुसार आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अवशेष 10 प्रकरणों में अवैध अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाया जाना सुनिश्चित करें। एसडीएम मिहींपुरवा (मोतीपुर) ने बताया कि तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) क्षेत्रान्तर्गत भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 0 से 15 कि.मी. में सरकारी भूमि पर कुल 184 अवैध अतिक्रमण पाये गये, जिसमें से 46 अतिक्रमण को हटा दिया गया। वर्तमान में 138 अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अवशेष है।

माननीय प्रधानमंत्री-भारत सरकार, श्री नरेन्द्र मोदी जी
एवं मुख्यमंत्री, श्रीमती रेखा गुप्ता जी

पूर्व केजरीवाल सरकार का कमाऊ पूत

सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के

ई.ई, ए.ई, कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा 11 वर्षो से विकास एवं निर्माण कार्य में बेहद घटिया निर्माण सामग्री व फर्जी बिल लगाकर।

करोड़ो के घोटाले व भ्रष्टाचार की जांच

श्रीमान निदेशक, सीबीआई, भारत सरकार से कराई जाएं।

छठ घाटो में टेन्ट, पानी टैंकर, बड़े नालो की साफ-सफाई, बॉउन्ड्रीवाल के फर्जी बिल लगाकरकिए गए करोड़ो के घोटाले और हरे-भरे पेड़ो को काटकर खुलेआम बेचा जा रहा है।

I&FC के श्री अशोक कुमार-(FC-III), ए.सुरेन्द्र कुमार (पीएनडी), अनुराग जैन (CD-I), विवेक चौहान (CD-II), शोभित जैन (CD-III), सोमनाथ कश्यप (CD-IV), बी.बी. नागपाल (CD-V), जे. नरेन्द्र सागर (CD-VI)
प्रदीप नैक (CD-VIII), पुनित डुडेजा (CD-IX), प्रशांत मिश्रा (CD-X), विवेक चौहान (CD-XI), गगन गौड़ (CD-XII), सुधीर कुमार आर्य (S.W-1 & CD-XIII), शिव कुमार (CD-XIV), जे. नरेन्द्र सागर (CD-XV)
एई, जे.ई ने ठेकेदारों की मिलीभगत से दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री और फर्जी बिल बनाकर कर रहे है अपना समाजवाद दूर!

भ्रष्टाचारियों व कमिशन खोरो का अड्डा बना

श्री सुधीर कुमार आर्य, ई.ई, सतर्कता कार्यालय: बसई दारापुर?

निवेदक: अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा (विज्ञापन)